

पत्र संख्या-वाद-अनुभाग/परिपत्र /2025-26 / 2526004
प्रेषक,

471

/ राज्य कर

आयुक्त. राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

अपर आयुक्त, राज्य कर, गौतमबुद्धनगर, जोन-नोएडा।
एवं समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, उ०प्र०।

(वाद-अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक 24 जून, 2025

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्या-186/1938001/11.05.2025 दिनांक 11.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें न्याय विभाग द्वारा रिट याचिका सं० 4058(रिट सी)/2025, श्रीमती मंगला व अन्य 2 बनाम उ०प्र० राज्य में पारित मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-19.05.2025 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ बेंच द्वारा अपने निर्णय में यह निर्देश दिये गये हैं कि मा० उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल किये जाने वाले प्रतिशपथ पत्र अन्तिम समय से पूर्व दाखिल किये जायें, जिससे प्रतिशपथ कोर्ट रिकार्ड पर समय से अध्ययन हेतु उपलब्ध हो सकें।

निर्णय के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

Before parting, we would like to put it on record that off late we find that whenever we order any officer to appear either in person or through video conferencing, invariably, we also ask the officer to submit an explanation on affidavit prior to the next date fixed in the matter. Such files are sent to our residence so that we may go through the affidavit, if any, filed by the officer, so that not much time is consumed during course of proceedings, however, almost everyday we find that the affidavits which are required to be filed before the date fixed are not on record, and invariably, they are filed on the date fixed in the Court itself. This is not at all a happy state of affairs, as, it unnecessarily wastes our time. On being confronted, Shri Manish Mishra, learned Additional C.S.C. informs that this is a difficulty which they are also facing, and this is on account of the fact **that the officers do not contact the C.S.C. office well in time so that such affidavits can be filed at least three or four days prior to the date fixed.** Shri Shailendra Kumar Singh, learned Chief Standing Counsel is also present. He says that he will look into the matter so that this situation does not arise in future. The officers would be better advised to contact the concerned Standing Counsel or C.S.C. well in advance so that the desired affidavit is filed promptly and is available in Court records for perusal of the Court, prior to the date fixed.

Copy of this order be sent formally to the Chief Standing Counsel for further action, and also to the Legal Remembrancer, U.P for ensuring the same.

अतः उक्त महत्वपूर्ण निर्णय को इस पत्र के साथ इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का संज्ञान लेते हुए मा० न्यायालय के समक्ष प्रति शपथ पत्र तीन या चार दिन पूर्व दाखिल कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

यह पत्र आयुक्त, राज्य कर के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।
संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अमरनाथ यादव)
अपर आयुक्त (विधि) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ०प०सं० व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-1-प्रमुख सचिव, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

2-अपर आयुक्त ग्रेड-1/2, (उच्च न्यायालय कार्य) राज्य कर, प्रयागराज/लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

3-संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।

24.6.25
अपर आयुक्त (विधि) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

तत्काल

संख्या - 186/1938001/11-5-2025

प्रेषक,

सुनील कुमार मण्डल
अनु सचिव,
उOप्रOशासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य कर विभाग,
उOप्रO, लखनऊ।

अपर आयुक्त/उC (सेवागृह/वाद) ✓

1092
आयुक्त
12.06.2025

राज्य कर अनुभाग-5

लखनऊ: 11-06-2025

विषयः: रिट याचिका संख्या-4058(रिट सी)/2025, श्रीमती मंगला व अन्य 2 बनाम
उOप्रO राज्य में पारित माO उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19-05-2025 का
अनुपालन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ
(न्याय विभाग), उOप्रO शासन के पत्र संख्या-136/सात-न्याय-अनुOप्रकोO/2025, दिनांक
03 जून, 2025, की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ
है कि कृपया न्याय विभाग द्वारा की गयी अपेक्षानुसार उपर्युक्त रिट याचिका में पारित
माO उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19-05-2025 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित
कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
Digitally signed by
(सुनील कुमार मण्डल)
Date: 11-06-2025
13:50:02

संख्या-186(1)/11-5-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित :-

1. - अनुभाग अधिकारी ,राज्य कर अनुभाग-1,2,3,4 एवं 5

आज्ञा से,

(सुनील कुमार मण्डल)

अनु सचिव

सदर मुद्रा

क्रमांक 138/सदर मुद्रा-अनुक्रमांक 0/2025

विभागीय मिह रावत

प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि विभाग

उ०प्र० शासन

सदर मुद्रा

सदर मुद्रा अवर मुख्य सचिव

प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन

अनुसूचना प्रकोष्ठ (न्याय विभाग)

लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2025

उपयुक्त मा० उच्च न्यायालय द्वारा केस नं०- 4058 (रिट सी)/2025, श्रीमती मंगला व अन्य 2 बनाम उ०प्र० राज्य में पारित आदेश दिनांक 19.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया उपर्युक्त विषयक सीनियर जजिस्ट्राट, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच के मा० रिट सी-2/गलकेओ/नं०-5145, दिनांक 23-05-2025 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का आदेश को जिसके माध्यम से केस संख्या-4058 (रिट सी)/2025, श्रीमती मंगला व अन्य 2 बनाम उ०प्र० राज्य में पारित आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की गयी है।

2- मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच द्वारा केस संख्या-4058 (रिट सी)/2025, श्रीमती मंगला व अन्य 2 बनाम उ०प्र० राज्य में पारित आदेश के मुख्य कार्यकारी अंश निम्नलिखित है:-

"Before parting, we would like to put it on record that off late we find that whenever we order any officer to appear either in person or through video conferencing, invariably, we also ask the officer to submit an explanation on affidavit prior to the next date fixed in the matter. Such files are sent to our residence so that we may go through the affidavit, if any, filed by the officer, so that not much time is consumed during course of proceedings, however, almost everyday we find that the affidavits which are required to be filed before the date fixed are not on record, and invariably, they are filed on the date fixed in the Court itself. This is not at all a happy state of affairs, as, it unnecessarily wastes our time. On being confronted, Shri Manish Mishra, learned Additional C.S.C., informs that this is a difficulty which they are also facing, and this is on account of the fact that the officers do not contact the C.S.C. office well in time so that such affidavits can be filed at least three or four days prior to the date fixed. Shri Shalendra Kumar Singh, learned Chief Standing Counsel is also present. He says that he will look into the matter so that this situation does not arise in future. The officers would be better advised to contact the concerned Standing Counsel or C.S.C. well in advance so that the desired affidavit is filed promptly and is available in Court records for perusal of the Court, prior to the date fixed

US (SKM)

(4)

06/06/25

468/25/25

21/06/25

5005

Demadaf
06/06/2025

श्री शलेंद्र कुमार सिंह
06.06.25

Copy of the order should be sent to the District Magistrate, District Jail, District Court, District Hospital and also to the Local Revenue Officer, District Jail, District Court, District Hospital.

3- अतः इस अवसर पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, साखनऊ बेंच द्वारा क्रम संख्या-4058 (रिड सी)/2025 शीघ्र ही प्रगता व अन्य 2 क्रमांक 4020, 4021 के तहत गणित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं खण्डपीठ साखनऊ में मा० के अधिकारीगण की ओर से दाखिल होने वाले आवेद एवं मा० न्यायालय में क्रम से क्रम सीमा या क्रम से एवं दाखिल किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक संशोधन

प्रमुख
(विनोद मिश्र रावत)

प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्श

संख्या- 136 /सात-न्याय-अनु०प्रकी०/2025, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० सरकार।
- 2- सीनियर रजिस्ट्रार, मा० उच्च न्यायालय, साखनऊ खण्डपीठ को उनके पत्र दिनांक 23-05-2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- मुख्य स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गजेन्द्र)

विशेष सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्श

During the proceedings of Case No. 4058 (WRIC) 2025, "Smt. Mangala and 2 Others Vs State of U.P. through Principal Secretary, Department of Revenue, Civil Secretariat, Lucknow and 4 Others". The Hon'ble Court had passed the following order on 19.05.2025:

Before parting, we would like to put it on record that off late we find that whenever we order any officer to appear either in person or through video conferencing, invariably, we also ask the officer to submit an explanation on affidavit prior to the next date fixed in the matter. Such files are sent to our residence so that we may go through the affidavit, if any, filed by the officer, so that not much time is consumed during course of proceedings. However, almost everyday we find that the affidavits which are required to be filed before the date fixed are not on record, and invariably, they are filed on the date fixed in the Court itself. This is not at all a happy state of affairs, as, unnecessarily wastes our time. On being confronted, Shri Manish Mishra, learned Additional C.S.C. informs that this is a difficulty which they are also facing, and this is on account of the fact that the officers do not contact the C.S.C. office well in time so that such affidavits can be filed at least three or four days prior to the date fixed. Shri Shailendra Kumar Singh, learned Chief Standing Counsel is also present. He says that he will look into the matter so that this situation does not arise in future. The officers may be better advised to contact the concerned Standing Counsel or C.S.C. well in advance so that the desired affidavit is filed promptly and is available in Court records for perusal of the Court, prior to the date fixed.

Cop. of this order be sent formally to the Chief Standing Counsel for further action and also to the Legal Remembrancer, U.P. for ensuring the same.

मैं अतः यहाँ से भेज रहा हूँ।

509

Enclosure, As above

Senior Registrar

High Court of Judicature at Allahabad
Lucknow

For Registrar General

गजेन्द्र
नाथ एन आर विधि परामर्श